रविवारीय

युद्ध विराम प्रश्नों पर विराम नहीं?

राजीव खण्डेलवाल
(लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

अमेरिका द्वारा कई बार बढ़ाई जाने के बाद खींची गई समय सीमा खत्म होने के मात्र 2 घंटे पूर्व ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच 14 दिनों के लिए युद्ध विराम होने पर अंतत: विश्व ने राहत महसूस की. युद्ध में कौन जीता कौन हारा? पर स्तंभकार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ, राष्ट्राध्यक्ष आकलन कर रहे हैं. लेकिन भारत की दृष्टि से एक भारतीय होने के नाते विश्व युद्ध (जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी) न होने के बावजूद विश्व को प्रभावित करने वाले इस युद्ध में हम कहां खड़े रहे? हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान की क्या भूमिका रही? इस पर हर किसी भारतीय को गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने प्रधानमंत्री को यह संदेश व फीडबैक दे सके, हमारी विदेश नीति कितनी सफल/असफल रही?

इसमें कोई शक नहीं कि 40 दिनों तक चल रहे युद्ध में अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ द्वारा अक्टूबर 2022 तक आतंकवादी वित्तपोषण के करण ग्रे लिस्ट में रखा गया पाकिस्तान विश्व पटल पर अप्रत्याशित एक शांति दूत के रूप में उभरा. लगातार नोबेल पुरस्कार का दावा करने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ भी बिगर दावे के दौड़ में शामिल हो गए हैं. विश्व पटल की राजनीति की यह एक नई स्थिति है, जहां युद्ध करने वाले, शुरू करवाने वाले, उत्प्रेरित करने वाले एवं युद्ध को भड़काने के लिए सैन्य सहायता देने वाला देश तथा आतंकी गतिविधियों को उत्जनित करने वाला देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष शांति के नोबेल पुरस्कार के संभावित स्वाभाविक दावेदार हो रहे हैं? युद्ध नहीं, बुध व गांधी की शांति व अहिंसा की बात करने वाला भारत नोबेल पुरस्कार के मैदान में प्रवेश करने के मौके की परिस्थितियों बनाने में असमर्थ रहा.

इसमें कोई शक नहीं, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का लगातार दौरे कर के मेहनत से अपनी एक विश्व गुरु की स्थिति बनाई है. लेकिन वर्ष 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पिछले 14 महीनों में

अमेरिका की विजय

- अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी ईरानी सभ्यता को प्राप्त करने की गंभीर धमकी के आगे वह ईरान, जिसने घोषणा की थी कि आगे वह अमेरिका से कभी बातचीत नहीं करेगा, को बातचीत के टेबल पर आने के लिए रजामंद होना पड़ा.
- दूसरी बड़ी उपलब्धि होर्मुज जलडमरूमध्य का समुद्री रास्ता विश्व के लिए खुल गया जो अमेरिका द्वारा ईरान पर थोपे गई युद्ध के कारण बंद हो गया था.
- अमेरिका ने अपने दोस्त भारत को छोड़कर पाकिस्तान से आतंकवादी देश का तमगा हटाकर उसे शांति दूत के रूप में स्थापित किया, जो आगे मिडिल ईस्ट खासकर मुस्लिम देशों में अमेरिका के लिए एक बड़ा टूल सिद्ध हो सकता है.
- ईरान के सर्वोच्च नेता एवं शिया संप्रदाय के विश्व के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खोमेनई सहित 40 से अधिक सर्वोच्च कमांडरॉ की हत्या कर हार्डकोर शासन परिवर्तन के दावे के बावजूद परिणाम आशानुकूल नहीं मिले.
- ईरान की हवाई शक्ति को नेस्तनाबूद करने का दावा. तथापि पूरी तरह सही नहीं.

प्रधानमंत्री की उक्त छवि पर गहरा आघात पहुंचा है. ऑपरेशन गंगा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन के बीच कुछ घंटों के लिए युद्ध रूकवाया. परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध विराम में ही नहीं बल्कि 40 दिन चले अमेरिका- इजरायल- ईरान के बीच युद्ध में वे कभी भी मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं दे पाए. वे खड़े कहां हैं? इस पर उन्हें गहन आत्मलोचन करना चाहिए. जिओ पॉलिटिक्स मैं अग्रणी भारत पाकिस्तान से हर मामलों में कई गुना बेहतर होने के बावजूद वह रोल अदा नहीं कर सका जो पाकिस्तान ने किया. इससे यह सिद्ध होता है एक कंगाल भूखहाल अनेकोनेक समस्याओं से ग्रस्त राष्ट्र भी संपन्न देशों के बीच अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. याद कीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की बात कही, बावजूद इस स्थिति के कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता से हमेशा स्पष्ट इनकार किया है. यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकन प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत ही व्यक्तिगत प्रगाढ़ संबंध है. ईरान से भी युद्ध आरंभ होने के पूर्व तक अच्छे ऐतिहासिक संबंधों की गाथा कही जाती रही, जहां महात्मा गांधी के नाम से सड़के, स्टेडियम, अस्पताल आदि है. 9 करोड़ जनसंख्या वाला ईरान अपनी सार्वभौमिकता को लेकर अमेरिका के सामने 56 इंच का सीना तानकर खड़ा हो सकता है, तब 140 करोड वाला भारत अपने स्वाभिमान व संप्रभुता को लेकर चुप क्यों? बैक-चैनल और शटल डिप्लोमेसी से बदनाम शहबाज शरीफ हो गए.

ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को समझौता वार्ता के लिए चुना. बेमन से ही सही, पाकिस्तान की इस कूटनीतिक सफलता से विश्व में पाकिस्तान की एक नए रूप के उभार को हमें स्वीकार करना ही होगा. यही हमारी विदेश नीति स्पष्ट रूप से असफल होती दिखती है. युद्धरत दो देशों को तुरंत युद्ध विराम पर सहमत कर आगे स्थाई शांति के लिए समझौता वार्ता के लिए तैयार कराने के एक इस कृत्य ने आतंकवादी गतिविधियों को चलाने व पनाह देने वाला पाकिस्तान को पूरे विश्व में शांति का मसीहा बना दिया. पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू होने के साथ सऊदी अरब जो ईरान का दुश्मन है, के साथ रक्षा संबंधी ट्रीटी करने के बावजूद, ईरान- अमेरिका युद्ध के दौरान न पूर्ण समर्थन न पूर्ण विरोध की नीति अपना कर ईरान से संबंधों का संतुलन बनाए रखा. हमारी मेंनस्ट्रीम मीडिया का तो दिवालिया ही निकल गया, जो बीच युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश को नकार रहा था. चीन भी पर्दे के पीछे चुप रहकर अपनी सहायक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था, जबकि हम रात में सो रहे थे.

ईरान की उपलब्धियां

- खोमेनई के 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की समाप्ति पर ईरान को सबसे बड़ा यह मिला कि उसके 10 सूत्री स्थाई शांति प्रस्ताव पर ही आगे शांति वार्ता (इस्लामाबाद टॉक) की जाएगी.
- दूसरी; ईरान की उपलब्धि यह रही कि होर्मुज जलडमरूमध्यके समुद्री रास्ते पर उसकी निगरानी और नियंत्रण बना रहेगा, भले ही जहाजों का आवागमन निर्बाध, बिना किसी चौथ वसूली के तुरंत शुरू हो जाएगा.
- तीसरा; इसराइल को बातचीत में शामिल किए बिना न केवल इजराइल ने इस अस्थाई युद्ध विराम को स्वीकार किया है, बल्कि उसने लेबनान पर हमला रोकने की घोषणा भी की है.
- ईरान अपने परमाणु संयंत्रों को बचाए रखने में सफल रहा.
- अयातुल्ला अली ख़ामेनेई व परिवार के कई सदस्यों की हत्या के बावजूद उनके बेटे मोजतबा ख़ामेनेई के नेतृत्व ने आयतुल्लाह की नीति को आगे बढ़ते हुए अपने नेतृत्व को मजबूत किया. फलस्वरूप युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व शासन परिवर्तन के लिए सड़क पर आए लाखों लोग शासन समर्थक हो गए, जो पावर स्टेशन की सुरक्षा के लिए सड़क पर आ गए.
- ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए समस्त प्रतिबंध स्थगित कर दिए गए.
- ईरान के यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार कर लिया गया जिसे आक्रमण करने का एक आधार अमेरिका ने बताया था.
- ईरान के तेवर को देखते हुए अमेरिका शीला उतारने की योजना क्रियान्वित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया बल्कि समझौते के तहत ईरान की सीमा के पास जो सेना की तैनाती की गई है, उसे अमेरिका वापस बुलाएगा.

नीतीश का जाना आरजेडी का ढलान

अंगेश कुमार
राजनीतिक विश्लेषक

ईरान - इजरायल, अमेरिका युद्ध और उससे उत्पन्न वैश्विक संकट उसके बाद सीज़फायर और अमेरिका ईरान समझौते के बीच भारतीय राजनीति इतिहास के पन्ने पर एक ऐसी कहानी लिखी और मिटाई जा रही है, जिसकी चर्चा छिटपुट होते हुए भी दिग्भ्रमित हो गई है। बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक का भी ध्यान संभवत: इस ओर नहीं गया, या वो भूल गए ऐसा नहीं कि बात करना जरूरी नहीं समझा हो पर फुर्सत नहीं मिली हो! संभवत: केंद्रीय सत्ता पर बैठे मठाधीश इस मुद्दे को ज्यादा हवा देना पसंद नहीं किए हो। हम बिहार में चोरी चोरी चुपके चुपके सत्ता परिवर्तन की पटकथा और इसके दूरगामी परिणाम की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। 2025 का बिहार चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था, बहुत सारे

> 2015 में जब लालू यादव की राजद मृतप्राय थी उस समय नीतीश कुमार ने अपने कंधे का सहारा देकर लालू जी की पार्टी को खड़ा कर दिया और बीजेपी तीसरे स्तर की पार्टी बन गई, जबकि 2014 के लोकसभा में मोदी अपराजेय घोषित हो चुके थे। संक्षेप में निष्कर्ष यही कहना है कि आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा। भेजे जा चुके हैं और बीजेपी की 45 साल की हसरत अब पूरी होती दिख रही है चाहे अनैतिक रूप से ही सही। तो इसका अंदाजा तो सबको है कि जो नासमझ लोग नीतीश कुमार के बेटे निशांत के भरोसे राजनीति करना चाह रहे हैं उन्हें अभी राजनीति के प्राथमिक पाठशाला का भी ज्ञान नहीं है।

मामलों में टेकऑफ (उड़ान भरने) वाला चुनाव था। हरियाणा दिल्ली महाराष्ट्र के प्रयोगशाला से निकला हुआ चुनावी जिन्न जिसे चुनाव आयोग एसआईआर (गहन मतदाता पुनरीक्षण) कहता हैं जबरिया बिहार में करवाया गया. 2024 के लोकसभा चुनाव में ढलान पर आए मोदी सरकार को नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे केंद्र सरकार चलाकी पर रही है। उससे पहले इंडिया एलायंस को तोड़ा गया. खैर मुख्य मुद्दे पर आते हैं; बीजेपी नहीं चाहती थी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन बीच चुनाव में पराजय होते देख घोषित करना पड़ा. फिर भी राजनीति समझने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा था कि नीतीश लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे। लेकिन बंगाल चुनाव से पहले ही उन्हें निबटा दिया जाएगा ऐसा भी नहीं माना जा रहा था। नीतीश कुमार के शासन प्रशासन की चर्चा हमारा उद्देश्य नहीं है; ना कि कौन आगमी मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश लालू रामविलास इत्यादि 1977 के जयप्रकाश आंदोलन के संपूर्ण क्रांति की फसल थे। ये बात दीगर है कि लालू यादव को छोड़ कर बाकी सभी अंततोगत्वा साम्प्रदायिक शक्तियों के गोद में खेलते दिखे. यद्यपि जयप्रकाश जी भी कांग्रेस और इंदिरा गांधी के विरोध में आरएसएस की तारीफ कर देश का कितना नुकसान किया उसका अंदाजा उन्हें नहीं रहा होगा ! भुगतान हमलोग कर रहे है. वही नीतीश कुमार जो पूर्ण भगवा धारी को अपने पद के लिए सत्ता में आने से रोकते रहे अंतत: निपटा दिए गए। तात्पर्य यह कि जेपी आंदोलन से निकले लोगों ने देश की सत्ता को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई, बिहार, उत्तरप्रदेश और हरियाणा दिल्ली, महाराष्ट्र गुजरात तक।

इस विरासत के अंतिम सत्ताधारी थे नीतीश कुमार जनता दल से निकल कर 1994 में जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव जी के साथ समता पार्टी की स्थापना किया. वैचारिक विरोध में 1997 में फिर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया, पुन: फिर 2003 में जनता दल यूनाइटेड का गठन नीतीश कुमार ने किया। तात्पर्य यह कि नीतीश और लालू की प्रतिबद्धता भले अलग अलग थी. परन्तु दोनों की राजनीतिक पिच तथाकथित सामाजिक न्याय एक रही है। और दोनों एक दूसरे को खाद पानी देते रहे है। जब एक कमजोर होता था तो दूसरा उसे जिंदा कर देता था। 2005 से विरोधी बना कर गाली देते हुए भी एक दूसरे को सहयोग और सहानुभूति देते रहे। जदयू जल्द ही समाप्त होने वाली पार्टी है, चाहे दो धरे में बंट जाए या कही विलय हो जाए। साथ ही लालू यादव जी के राजनीतिक अवसान के बाद अब उनकी पार्टी को जीवंत और प्रासंगिक रखने वाली जदयू जब खुद समाप्त हो जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल की भी प्रासंगिकता जाती रहेगी, यद्यपि कुछ दिन तक टिकेगी. ऐसे में बीजेपी के विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को पुन: बिहार में उभरने के लिए उपयुक्त समय, उपयुक्त जमीन और अवसर मिलने की पूरी संभावना है। और यही से भारत की राजनीतिक धुरी फिर से एक बार घूमने जा रही है, जिसका अंदाजा संभवत: कम लोगों को है. जाति की राजनीति पर अब रोजगार, शिक्षा, उद्योग पलायन का मुद्दा प्रभावी बनेगा, और युवाओं को पुन: राजनीति में लाकर परिवारवाद के थकाऊ उबाई राजनीति से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

नक्सली नेताओं की मेन-टू-मेन मार्किंग

कृष्णमोहन झा
राजनीतिक विश्लेषक

देश को नक्सलवाद की चुनौती से मुक्त कराने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो व्यापक, बहुस्तरीय और परिणामोन्मुख रणनीति लागू की गई है, वह अब ऐतिहासिक सफलता के रूप में सामने आ रही है। यह केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित प्रयास नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें सुरक्षा, विकास, पुनर्वास और इकोसिस्टम के ध्वस्तीकरण को समान महत्व दिया गया। अमित शाह के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता रही है—तेज निर्णय और जमीनी जरूरतों की तुरंत पूर्ति। उदाहरण के तौर पर, जब यह सामने आया कि जिला रिजर्व गार्ड के जवान बिना पर्याप्त हथियारों के ऑपरेशन पर जा रहे हैं, तो मात्र 20 दिनों के भीतर उन्हें आधुनिक हथियार उपलब्ध करा दिए गए। इसी प्रकार, सुरक्षाबलों के लिए एंटी-स्पाइक बूट्स की मांग को भी तुरंत पूरा किया गया, जिसके बाद स्पाइक की

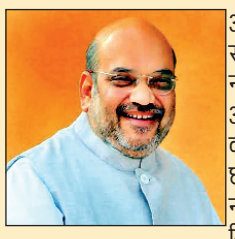

> अमित शाह के निर्देश पर बनाई गई नई पुनर्वास नीति ने सामूहिक आत्मसमर्पण को संभव बनाया। जेल में बंद नक्सलियों को भी मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए गए। असम मॉडल का अध्ययन कर उसे लागू करने से इस नीति को और प्रभावी बनाया गया। 21 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान ही दिसंबर 2025 तक नक्सलमुक्त भारत का रोडमैप तैयार कर लिया गया था, जिसकी औपचारिक घोषणा अगस्त 2024 में की गई। गृह मंत्री के नेतृत्व में आसूचना ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के बीच अभूतपूर्व समन्वय स्थापित हुआ। ऑपरेशन और आत्मसमर्पण के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया—जहां एक ओर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा और डीआरजी ऑपरेशन संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पत्रकारों और परिवारजनों की मदद से आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज नक्सलवाद का नामलेवा शायद ही कोई हो। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह की स्पष्ट सोच, मजबूत इच्छाशक्ति और तेज़ निर्णय क्षमता का बड़ा योगदान है। सुरक्षा, विकास और विश्वास के इस त्रिकोणीय मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति स्पष्ट हो और नेतृत्व दृढ़, तो दशकों पुरानी चुनौतियों का समाधान भी संभव है। नक्सलमुक्त भारत का सपना अब दूर नहीं, बल्कि एक साकार होती वास्तविकता है।

वजह से जवानों के घायल होने की घटनाएं लगभग समाप्त हो गईं। घायल जवानों को एयर एम्बुलेंस से तुरंत इलाज के लिए एयरलिफ्ट करने की सुविधा भी गृह मंत्री के निर्देश पर सुनिश्चित की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियाद नेल्लार योजना ने एक सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। पहले जहां ग्रामीण सुरक्षा कैंपों का विरोध करते थे, वहीं अब वही लोग विकास कार्यों को देखकर स्वयं कैंप की मांग कर रहे हैं। हर सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाकों तक भी सुरक्षा बलों की पहुंच संभव हो सकी। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के तहत नक्सलवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसमें सकारात्मक सहयोग दिया। सरकार की ओर से संयुक्त पूछताछ समिति का गठन, माओवादी समर्थकों पर कानूनी कार्रवाई और उनके शहरी नेटवर्क—कानूनी व वित्तीय आधारों—पर प्रहार किया गया। तेंदूपत्ता जैसे स्रोतों से होने वाली उगाही पर प्रतिबंध लगाकर नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़ी गई। साथ ही, जांच और अभियोजन में युवा व ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती कर मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित किया गया। मानवीय और तकनीकी इंटेलिजेंस के समन्वय से सटीक और सफल ऑपरेशन संभव हुए। बड़े नक्सली नेताओं की मैन-टू-मैन मार्किंग के लिए युवा आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई, जिससे बसवराजू जैसे शीर्ष नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई संभव हो सकी। आईईडी की पहचान और निष्क्रिय करने के लिए डीआरडीओ के सहयोग से नई तकनीकों को विकसित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ओटीपी आधारित और प्रोग्रामेबल डेटोनेटर की मंजूरी दी गई, जिससे विस्फोटों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने में भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने निर्णायक भूमिका निभाई। जब तक बल स्वयं उपकरण नहीं खरीद सके, तब तक सेना से आधुनिक हथियार और तकनीक उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों और अधिकारियों ने लगातार मेहनत की। हेरॉन ड्रोन, स्नाइपर राइफल, डब्लूएचएपी वाहन और पोर्टेबल वी—सैट जैसी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई गईं। साथ ही, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य बलों से समन्वय स्थापित कर ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के हस्तक्षेप से कई महत्वपूर्ण विकास कार्य तेजी से पूरे हुए। बीजापुर और नारायणपुर में पुल निर्माण, मोबाइल नेटवर्क विस्तार, और दूरदराज़ इलाकों में बस सेवाओं की शुरुआत इसका उदाहरण हैं। जहां फंडिंग में देरी हो रही थी, वहां उनके हस्तक्षेप से मात्र दो दिनों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से फंड जारी हो गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बस योजना और मोबाइल टावर योजना को भी उनके निर्देशों से गति मिली।

व्यंग्य

कुंडी न खड़काओ राजा...!

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

जब से यह गाना सुना है तब से इस गाने पर मेरा चिंतन मनन और स्पेशल इंटेंसिव रीडिंग चल रही है कि आखिर नायिका इस गाने में नायक से क्या कह रही है. वह नायक जिसका नाम शायद राजा रहा होगा से कुंडी खड़काने से क्यों मना कर रही है? क्या नायिका पर्यावरण प्रेमी है जो नायक को कुंडी न खड़काने का इंस्ट्रक्शन दे रही है या बोल्डनेस होने के बावजूद भी नायिका में इतनी शर्म ओ हया बाकी है कि वह समाज की लोक लाज की इज्जत बनाए रखने के लिए नायक से कुंडी खडकाने को मना कर रही है. यह बहुत ही खुशी की बात है कि नायिका लोक संस्कृति के प्रति इतनी जागरूक है कि वह नायक से कुंडी न खड़काने कि रिक्वेस्ट कर रही है.

यह भी हो सकता है कि नायिका पर्यावरण प्रेमी हो और वह नहीं चाहती हो कि क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण हो और लोगों की निंद्रा में खलल पड़े और लोग जाए. नायिका जानती है कि क्षेत्र के मर्द तो यह नज़ारा देखकर अनदेखा कर देंगे, पर आसपास की बैकवर्ड लेडीज़ क्या? वो खुसुर पुसुर कर उसे बदनाम कर सकतीं हैं. यह सब जानकर मन को कितना सुकून मिलता है कि नायिका कितनी समझदार है जो इतना सोच रही है.

यह हमारे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि आज के जमाने में नायिका इतनी बोल्ड होने के बाद भी लोकलाज के प्रति कितनी सतर्क है. नारी के लोकलाज के प्रति सतर्क तो हमारे देश के एक राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं. जिन्होंने नारी की लाज की रक्षा के लिए एक महामंत्र दिया है. उन्होंने अपने सूबे की महिलाओं बेटियों को सुझाव दिया है कि वो रात को आठ बजे के बाद सड़कों पर न निकलें. यह हुई न सौ बात की एक बात, न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी. इसे कहते हैं कि हरड़ लगे न फिटकरी रंग चोखा का चोखा.

काफ़ी गंभीर शोध करने के बाद पता चला है कि यह गाना गब्बर इज़ बैक फिल्म का है और इसे नेहा कक्कड़ ने गाया है. इस गाने को चित्रांगदा सिंह और अक्षय पाजी पर फिल्माया गया है. इस गीत को लिखा है कुंवर जुनेजा ने. अब चूंकि नायक गब्बर है तो नायिका द्वारा उसे यह हिदायत देना पूरी तरह माकूल है कि है राजा तुम कुंडी मत खड़काओ, बिना किसी लाज शर्म के सीधे अंदर आ जाओ. यहां तुम से किसी में भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है. फिर तुम तो ठहरे गब्बर, भला तुम से कोई भी कुछ कहने की हिम्मत कैसे करेगा. कितनी ही नारी की इज्ज़त लुट जाए यहां कोई कुछ नहीं कहता है. लोगों की आंखों का पानी सूख चुका है. यहां सब के सब बापू के तीन बंदरों के समान अपनी आंख, कान और मुंह बंद किए रहते हैं. यहां डगर डगर पर दुर्योधन और धृतराष्ट्र छुपे बैठे हैं. इसी कारण तो शायद नायिका भी इतनी बोल्ड बन गई है. जो खुल्लम खुल्ला कह रही है.. कुंडी न खड़काओ राजा धीरे से अंदर आ जाओ राजा....!

फिल्मों में एक वह भी ज़माना था जब नायिका को चांद देखने के बहाने से बुलाया जाता था. भंवरे को भी कहा जाता था कि भंवरे...धीरे से आना बगियन में. अब नायक बीच सड़क पर ऑफर देता है.. चलती क्या नौ से बारह. लगता है कि नायक और नायिकाएं बहुत सशक्त हो गई हैं. वो कहती है कि आंख मारे, ओ लड़का आंख मारे.

लेकिन देखिए जमाना कितना बदल गया है. पहले के जमाने में कहते थे कि फिल्में समाज का दर्पण होतीं है. तब के जमाने का दर्पण आज के जमाने को देख लेता तो खुद- ब -खुद टुकड़े - टुकड़े हो जाता. आज का इंसान ही है जो पत्थर बन गया है और उसके संस्कार पथरा गए हैं. अब नायक गाता है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हम को वो गुजारा जमाना याद है.